

## आरंगजेब की राजपूत नीति

आरंगजेब के काल में मुगलों की राजपूत नीति में व्यापक बदलाव आया। कई विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा है कि आरंगजेब ने गैर मुस्लिमों के प्रति कहरवादी धार्मिक नीति का अनुगमन किया जिससे मुगल राजपूत नीति में तनाव आया और मारवाड़ एवं मैवाड़ से सम्बन्ध विच्छेद हुआ। इस संदर्भ में प्रायः यह भी कहा जाता है कि इसने एक प्रकार से अकबर की राजपूत नीति को पूरी तरह से उल्टा दिया जिससे साम्राज्य को काफी नुकसान हुआ तथा इसके विघटन का प्रमुख कारण बना।

लेकिन वास्तव में देखा जाये तो सामान्य मान्यता के विपरीत आरंगजेब की राजपूत नीति उसके पूरे शासन काल में एक जैसी नहीं रही। विभिन्न कारणों के दबाव में समय के साथ उसकी राजपूत नीति में क्रमिक बदलाव आया। आरंगजेब की राजपूत नीति का विकास तीन चरणों में हुआ। -

(क) पहला चरण - 1658 ई. से 1668 ई. के बीच

(ख) दूसरा चरण - 1668 ई. से 1677 ई. के बीच

(ग) तीसरा चरण - 1677 ई. से 1707 ई. के बीच

आरंगजेब की राजपूत नीति का प्रथम चरण 1658 ई. से 1668 ई. के बीच का रहा। इसमें उसके राजपूतों के साथ सम्बन्ध काफी मजबूत एवं प्रगाढ़ रहे। इस दौरान राजपूत मुगल साम्राज्य के भागीदार एवं प्रमुख शिथ्यार बने रहे। यहाँ तक कि शाहजहाँ की तुलना में राजपूत अमीरों को अधिक सम्मान एवं उच्च और दे दिये गये। जयसिंह एवं जसवन्त सिंह को न केवल 7000 का मनसब दिया गया बल्कि क्रमशः दक्कन एवं गुजरात का सूबेदार भी बनाया गया। उत्तराधिकार युद्ध में दो बार दल बदलने वाले जसवन्त सिंह को काफी



दी गई तथा मेवाड़ के राजा से भी सम्बन्ध बनाये गये।

फिर भी इस चरण के अंतिम दिनों में संबंध में कुछ शिथिलता के संकेत मिलते हैं। मेवाड़ के राजा राज सिंह को शर्ही अनुमति के बिना किशनगढ़ पर हमला करने तथा राजकुमारी चारुमति से विवाह करने के लिये न केवल स्पष्टीकरण मांगा गया बल्कि जवाब से सतृप्त न होने पर दंड स्वरूप दवा लीया तथा बाँसवाड़ा का क्षेत्र दिन लिया गया। साथ ही शिवाजी के संबंध में राजपूतों की भूमिका को लेकर भी औरंगजेब सशंकित हुआ। दरअसल शाइस्ता खान की दावनी पर शिवाजी का हमला, फिर शिवाजी का आगरा से पलायन करना आदि घटनाओं ने जयासिंह के विरोधियों को उसके खिलाफ बादशाह के कान भरने का अनुकूल अवसर दिया।

कुल मिलाकर देखा जाये तो इन घटनाओं की वजह से औरंगजेब एवं राजपूतों के रिश्ते में थोड़ा ठंडापन भर आया किंतु मुगल राजपूत सम्बन्ध पूर्ववत् बने रहे।

औरंगजेब की राजपूत नीति का दूसरा चरण 1668 ई. में प्रारंभ हुआ तथा 1677 ई. तक चला। यह वर्ष दौड़ था जब औरंगजेब अनेक परेशानियों से घिरा हुआ था। वास्तव में 1665 ई. के ही उसके सामने एक के बाद एक गंगौर चुनातियाँ आनी लगी जिनसे शिवाजी का आगरा से भागना, जाट विद्रोह, सतनामी विद्रोह, मराठा विद्रोह और इसी के साथ क्तिनीय संकट की स्थिति औरंगजेब ने साम्राज्य की एकता एवं अखण्डता बनाये रखने के लिए मुसलमानों को गोलबन्द करने चाही और इसके लिये राज्य के इस्लामी चरित्र पर बल दिया। इसके तहत कई कहरवादी कदम उठाये जिससे सहिवादी तत्वों को बल मिला जिनसे राजपूतों को केन्द्र से दूर संकटग्रस्त क्षेत्रों में नियुक्त किया गया, राजपूतों को



इस दौरान किसी राज्य की सूबेदारी नहीं की गई तथा कई अन्य आइटमों  
 वास्तुमन्त्रियों को अपेक्षाकृत निम्न पदों पर नियुक्त किया। उदाहरण-  
 स्वरूप असवन्तसिंह को नामरूप का थानेदार बनाकर भेजा गया जो  
 यकीनत उनकी पदावनी थी। इसी तरह राजसिंह को सैनिक अभि-  
 थान पर बंगाल भेजा गया तां उल्लेख की सूबेदारी नहीं ली गई।  
 इस तरह दूसरे चरण में उनके सम्बन्ध में मनोमानित्व की स्थिति आ गई  
 थी।

आरंगजेब की राजपूत नीति का तृतीय चरण 1678 ई.  
 में प्रारंभ हुआ। इस चरण में मालवाइ एवं मेवाड़ से सम्बन्धों में कड़वाहट  
 आयी। यदुनाथ लखार जैसे लखारों की मान्यता है कि आरंगजेब एक  
 धर्मन्ध्र शासक था। वह राजपूतों की शक्ति का विनाश करना चाहता  
 था और इस उद्देश्य से उसने मालवाइ पर वहाँ के शासक असवन्त  
 सिंह की मृत्यु के बाद अधिकार कब्जा चाह्य मगर दुर्गादास के नेतृत्व में  
 राजपूत सरदारों ने प्रबल विरोध किया जो लगभग बीस वर्षों तक चला।  
 इसमें काफी धन-जन की हानि हुई। यद्यपि राजपूत मुगलों के समर्थक  
 एवं सेवक थे लेकिन जब आरंगजेब ने उनके खिलाफ दमनकारी नीति  
 अपनायी तो उन्होंने भी मुगल साम्राज्य के विनाश में दूर धार का  
 काम किया।

लेकिन नवीनतम शोध उपरोक्त धारणाओं को नकार-  
 रते हैं। रामप्रसाद त्रिपाठी, अतहर अली, एवं लतीफ चन्द्र आदि ने  
 तत्कालीन राजनीतिक, आर्थिक कारणों के परिपक्ष में उसकी राजपूत  
 नीति को मूल्यंकन किया है एवं बताया है कि वह ने तो राजपूतों को  
 कट्टर विरोधी था और ना ही उनका विनाश करना चाहता था। मालवाइ  
 का प्रश्न शुरु रूप से उत्तराधिकार से जुड़ा मामला था, दूसरे अर्थ  
 भी कई राजपूत वंश उसकी सेवा में थे।

निश्चय ही आरंगजेब-मालवाइ सम्बन्ध



मुगल-राजपूत सम्बन्ध में थोड़ी कड़वाहट व्यक्त थी। मारवाड़ का प्रश्न 1678 ई. में पूरा हुआ जब असफ़त सिंह बिना किसी उत्तराधिकारी के मर गये। अतएव उत्तराधिकारी के अभाव में राजगामिता कानून के तहत उनके राज्य को केन्द्रीय प्रशासन के तहत ले लिया गया। तभी असफ़त सिंह की गर्भवती की पत्नियाँ ने दो बच्चों का जन्म दिया जिसमें से एक की मृत्यु अशवावस्था में ही हो गयी। अब राठौर सरकारों ने दुर्गादास के नेतृत्व में असफ़त सिंह के पुत्र अजीत सिंह को गद्दी देने की मांग की। औरंगजेब प्रशासनिक कारणों से बालक को गद्दी देने से मना कर दिया। अतएव राठौर सरकारों ने दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। औरंगजेब इस विद्रोह को कुचलने के लिये काफी जोर लगाया। 1680-81 ई. में स्थिति तब आर बिगड़ गई जब मेवाड़ के राज्य राजसिंह जो अजीत सिंह का मामा लगता था, मारवाड़ का समर्थन करते हुए विद्रोह में शामिल हो गया। औरंगजेब तब अजीत सिंह के चचेरे भाई इन्द्र सिंह को मारवाड़ का शासन सूत्र सौंपा लेकिन इस राठौर सरकारों ने अपना समर्थन नहीं दिया। इसी समय अकबर द्वितीय भी इन विद्रोहियों से जुड़ गया। समय की नजाकत को देखते हुए औरंगजेब ने मेवाड़ के शासक से संधि कर ली। अंततः 1688 ई. में मारवाड़ से भी समझौता हो गया एवं अजीत सिंह को मान्यता दे दी गई।

इस तरह जब हम औरंगजेब की राजपूत नीति पर समग्र दृष्टि डालते हैं तो पाते हैं कि अरब में औरंगजेब ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया। दरअसल इसकी आरंभिक राजपूत नीति लगभग वैसी ही थी जैसा अकबर एवं जहाँगीर की थी किंतु आगे चलकर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनीं जिससे मुगल-राजपूत रिश्ते में शिथिलता आने लगी और जिसकी परिणति मारवाड़ एवं मेवाड़ में मुगलों



के खिलाफ विद्रोह के रूप में हुई। किंतु यह मुगल-राजपूत सम्बन्धों का अंत नहीं था, क्योंकि अनेक राजपूत जैसे आमेर, बिकानेर, बूंदी, कोटा आदि अभी भी मुगल सेना में बने रहे। इतना ही नहीं कुछ ही दिनों के बाद मुवाड़ से सम्झौता हो गया तथा माखाड़ से भी सम्बन्ध बहाल हो गये। लेकिन इस बदलाव के बावजूद राजपूत न तो अब मुगल साम्राज्य के प्रमुख साम्प्रदाय रहे और न शक्तिपार।

इसमें दो राय नहीं कि आरंगजेब के समय पहले से चली आ रही राजपूत नीति में कुछ संशोधन जरूर हुये जो कुछ तो परिस्थितिजन्य थी तथा कुछ उसकी अपनी हठधर्मिता, राजनीतिक अदक्षिणता एवं नीतिगत भूलों का परिणाम। चार्हे कारण जो रहे थे इसका प्रभाव मुगल साम्राज्य की शक्ति एवं दृढ़ता पर पड़ा। लेकिन इसे मुगल साम्राज्य के पतन के लिये एकमात्र कारण बनाना समीचीन नहीं है। क्योंकि मुगल साम्राज्य के अंदर भी आधारभूत संरचनात्मक साम्राज्य टिकी हुई थी। तभी इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि इसके कारण गैर-मुस्लिम आबादी में बादशाह की साख में कमी आयी तथा इसके मनसूबों के प्रति आशंकाये पैदा हुयी। इस तरह निश्चय ही इस समामेलन की प्रक्रिया का आधार लगा जिस अकबर ने शुरू किया था